सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 06 फाल्गुन, 1942 (श०)
25 फरवरी, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 05

(1)	कृषि विभाग	01
(2)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	01
(3)	नगर विकास एवं आवास विभाग	01
(4)	सहकारिता विभाग	01
(5)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	01
	कुल योग --	05

राशि खर्च करना

10. श्री सुधाकर सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत 16 अरब 92 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, परंतु अभीतक स्वीकृत राशि खर्च नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त राशि कबतक खर्च करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आर्सेनिक मुक्त जलापूर्ति करना

11. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में आर्सेनिकयुक्त जल के सेवन से लोगों को कैंसर, एनीमिया आदि बीमारी होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के बेगूसराय, मुजफ्फरपुर सहित 18 जिले में 2 करोड़ से अधिक की आबादी आर्सेनिकयुक्त जल से प्रभावित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में आर्सेनिक मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कौन-सी कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

12. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में कचरा प्रोसेसिंग प्लांट नहीं रहने के कारण पटना के रामचक बैरिया सहित राज्य के सभी शहरों में जगह-जगह पर कचरे का अम्बार लग गया है, यदि हाँ, तो सभी नगर निकाय क्षेत्रों में अभीतक कचरा प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाये जाने का क्या औचित्य है ?

मक्का की खरीद करना

13. श्री (मो0) शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में पैक्सों के माध्यम से किसानों के धान तथा गेहूँ की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सभी 38 जिलों के किसानों से पैक्स के माध्यम से मक्का की खरीद नहीं की जाती है, जिससे किसानों को मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पैक्स के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीद करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकार ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय एजेंसियों के सहयोग से मक्का अधिप्राप्ति की संभावना पर राज्य सरकार विचार कर रही है ।

दोषी पर कार्रवाई

14. श्री ललित कुमार यादव--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 फरवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''खाद्य आयोग ने पकड़ी चोरी, सौ के बदले 90 किलो अनाज की आपूर्ति'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य खाद्य आयोग की उच्चस्तरीय जाँच टीम ने जाँच में पाया है कि राज्य में गरीबों को मिलने वाले सस्ते अनाज जो जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से दिया जाता है, उसमें एफ0 सी0 आई0 के गोदाम से लाभुकों तक पहुँचते-पहुँचते 20 प्रतिशत कम अनाज लाभुकों को मिल पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--नहीं । राज्य खाद्य आयोग द्वारा इस प्रकार की कोई सूचना/प्रतिवेदन राज्य सरकार को नहीं दिया गया है । सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग ने अपने पत्रांक 66, दिनांक 18 फरवरी, 2021 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि दिनांक 5 फरवरी, 2021 को समाचार-पत्र में ''खाद्य आयोग ने पकड़ी चोरी, सौ के बदले 90 किलो अनाज की आपूर्ति'' शीर्षक से प्रकाशित खबर के संबंध में माननीय अध्यक्ष के द्वारा किसी भी दैनिक समाचार-पत्र को ऐसा कोई आधिकारिक बयान अथवा प्रेस विज्ञप्ति नहीं दिया गया है । सरकार किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लेती है और प्रत्येक मामले में यथोचित कार्रवाई करती है ।

पटना :
दिनांक 25 फरवरी, 2021 (ई0) ।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 104(एल0ए0), 2020-21-डी0टी0पी0-550